

कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा उछाल

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा संकट, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल महंगा

नई दिल्ली, 13 जुलाई अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दिखाई देने लगा है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती हलचल और संभावित आपूर्ति बाधाओं की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है.

ब्रेंट कच्चा तेल 78 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल भी 73 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और तेजी देखने



को मिल सकती है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य बना संकट का केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं. यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20 प्रतिशत

हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है. ऐसे में अगर इस मार्ग पर किसी भी तरह की रुकावट आती है तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. ईरान की ओर से इस मार्ग को बंद करने की धमकियाँ और दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई ने बाजार में चिंता बढ़ा दी है. तेल कीमतों में तेज बढ़ोत

तेल बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक तनाव जारी रहने पर कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है , अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं. अमेरिकी सेना की ओर से हॉर्मुज क्षेत्र में ईरानी मिसाइल प्रणालियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं. इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों पर कार्रवाई का दावा किया है. इस घटनाक्रम ने तेल उत्पादक देशों और वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ा दी है.

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ ही निवेशकों ने तेल बाजार में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है.

जून में खुदरा महंगाई दर बढ़ कर 4.38 प्रतिशत पर

नयी दिल्ली, 13 जुलाई परिचम एशिया संकट और मानसून की चिंताओं के बीच देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर जून 2026 में बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गयी.विश्लेषकों के अनुसार, नयी सीरीज होने के बाद 16 महीने में मुद्रास्फोति का यह उच्चतम स्तर है. इससे रिजर्व बैंक पर नीतिगत ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बन सकता है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मई में खुदरा मुद्रास्फोति 3.93 प्रतिशत (संशोधित आंकड़ा) थी. जून माह में बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, परिवहन सेवाओं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई.

भारत का व्यापार घाटा 59 प्रतिशत बढ़ा



किया गया, जो बाजार एक सर्वे के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने जून में व्यापार घाटा करीब 26.63 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था. यह आंकड़ा पिछले महीने मई के 28.21 अरब डॉलर के घाटे से भी

ज्यादा है. वहीं, पिछले साल जून में भारत का व्यापार घाटा 19.10 अरब डॉलर था आयात में तेजी और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने व्यापार घाटे को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

भारत का अमेरिका को निर्यात भी अप्रैल और मई के दौरान बढ़कर 17.29 अरब डॉलर पहुंच गया. कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और कमजोर रुपये ने भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिया है. इसी वजह से कई वैश्विक संस्थानों ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान बनाए रखा है अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भारत का रुख बढ़ते आयात खर्च और निर्यात को बनाए रखने की चुनौती के बीच भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहा है. सरकार बेहतर शर्तों के लिए बातचीत जारी रखना चाहती है.

सेबी कर्मचारियों के लिए नए सख्त नियम

शेयर निवेश और नौकरी बदलने पर बड़ी निगरानी

निजी निवेश और उपहार लेने के नियमों में भी बदलाव

नई दिल्ली, 13 जुलाई भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी ने अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों और आचार संहिता को और सख्त कर दिया है.

नए नियमों के तहत कर्मचारियों के शेयर बाजार में निवेश, नौकरी बदलने, उपहार स्वीकार करने और हितों के टकराव से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. सेबी ने कर्मचारी सेवा संशोधन विनियम, 2026 के तहत कई नए प्रावधान लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य नियामक संस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है.

सेबी ने नए नियमों में परिवार और आश्रितों की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है.अब इसमें शामिल होंगे: गोद लिए गए बच्चे, सीतेले बच्चे, आर्थिक रूप से कर्मचारी पर निर्भर अन्य व्यक्ति

इस बदलाव के बाद निवेश और जानकारी साझा करने से जुड़े नियमों का दायरा भी बढ़ जाएगा.



कर्मचारियों को अब अपने परिवार से जुड़े निवेश की जानकारी भी अधिक स्पष्ट रूप से देनी होगी. सेबी ने इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो साल की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि तय की है. इस अवधि के दौरान पूर्व कर्मचारी किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से सेबी के सामने किसी भी मामले में पेश्वी नहीं कर सकेगे. इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी नई नौकरी के लिए बातचीत शुरू करता है तो उसे इसकी जानकारी एक महीने के अंदर सेबी को देनी होगी.

सेबी ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के निजी निवेश नियमों को भी कड़ा किया है. शेयरों में नया निवेश नहीं कर सकेगे. इक्विटी में बदलने वाली प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकेगे. वायदा और विकल्प जैसे डेरिवेटिव बाजार में नया निवेश नहीं कर सकेगे.

इसके साथ ही सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि किन सामाजिक अवसरों पर और किस प्रकार के पारंपरिक उपहार स्वीकार किए जा सकते हैं. सेबी का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के काम में निष्पक्षता बनाए रखना और किसी भी तरह के हितों के टकराव को रोकना है. शेयर बाजार नियामक होने के कारण सेबी के कर्मचारियों पर आम कर्मचारियों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है. ऐसे में नए नियम संस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.

शुरुआती गिरावट से उबरे शेयर बाजार

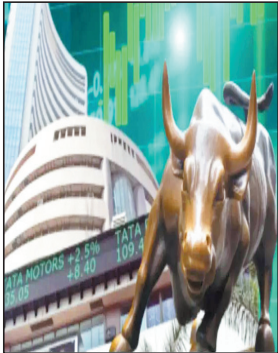
47.01 अंक चढ़ा संसेक्स

4.10 अंक आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 13 जुलाई आईटी कंपनियों में लिवाली के दम पर घरेलू शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती गिरावट से उबरते हुए अंत में मामूली बढ़त में बंद हुए.

बीएसई का संसेक्स सुबह 604 अंक नीचे खुला था. हालांकि दोपहर बाद हुई लिवाली से यह 47.01 अंक (0.06 प्रतिशत) चढ़कर 77,616.40 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 4.10 अंक (0.02 प्रतिशत) की बढ़त में 24,211 अंक पर रहा.

मझौली और छोटी कंपनियों में भी लिवाली रही. निफ्टी



मिडकैप-50 सूचकांक 0.17 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100

संसेक्स की कंपनियों में टीसीएस का शेयर करीब साढ़े पांच प्रतिशत और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर पांच प्रतिशत बढ़ा. टेक महिंद्रा और इंफोसिस में तीन से साढ़े चार प्रतिशत की तेजी रही. एनटीपीसी का शेयर दो प्रतिशत बढ़ा. कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर पौने दो फीसदी से अधिक की बढ़त में रहा. पारपरिइ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में भी तेजी रही.

एक गलती से खाली हो सकता है बैंक खाता

नई दिल्ली, 13 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई टूल का इस्तेमाल आज तेजी से बढ़ रहा है. चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे टूल लोगों के काम को आसान बना रहे हैं, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने इन्हें ठगी का नया माध्यम बना लिया है.

एआई सरस्वता, मुफ्त सुविधा और विशेष ऑफर के नाम पर ठग लोगों को फर्जी वेबसाइट और नकली भुगतान पेज के जाल में फंसा रहे हैं. थोड़ी सी लापरवाही से बैंक खाते की जानकारी चोरी

हो सकती है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. एआई टूल के नाम पर शुरू हुआ ठगी का नया खेल साइबर अपराधी अब लोकप्रिय एआई सेवाओं की मांग का फायदा उठा रहे हैं. वे चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे टूल के नाम पर नकली वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लगती हैं.इन वेबसाइटों पर मुफ्त सुविधा, सस्ते सदस्यता शुल्क या विशेष उन्नत संस्करण देने का लालच दिया जाता है.

नौकरी छोड़ शुरू किया प्राकृतिक उत्पादों का कारोबार वारखा के चावल साबुन और मसूर दाल स्क़ब की विदेशों तक मांग

जमशेदपुर, झारखंड, 13 जुलाई आज के समय में जहां ज्यादातर युवा अच्छी नौकरी और ज्यादा वेतन को सफलता मानते हैं, वहीं जमशेदपुर की वारखा ने अपने जुनून को पहचानकर एक अलग रास्ता चुना.

हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी होने के बावजूद उन्हें अपने काम में संतुष्टि नहीं मिल रही थी. इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर प्राकृतिक उत्पादों का कारोबार शुरू किया. कड़ी मेहनत और नए विचारों के दम पर



आज उनके बनाए चावल के साबुन, मसूर दाल के स्क़ब और अन्य प्राकृतिक उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जा रहे हैं.

हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने वाली वारखा ने महसूस किया कि बाजार में

त्वचा से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. वहीं, कई सौंदर्य उत्पादों में रासायनिक पदार्थों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है. इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपनी मां के साथ मिलकर 'डिवाइन क्राफ्ट बाय वारखा' नाम से अपना कारोबार शुरू किया. शुरुआत में उनके सामने कई परेशानियां आई. सीमित संसाधनों के साथ ग्राहकों तक पहुंच बनाना और लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी.

वीईएफ ने पहल का विस्तार दिल्ली तक किया

नयी दिल्ली, 13 जुलाई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल 'यस/सिटीज' नेटवर्क का विस्तार दिल्ली तक हो गया है. फोरम का यह एक तेजी से बढ़ता हुआ अभियान है, जो शहरों को उनकी गंभीर शहरी चुनौतियों और विकास संबंधी आकांक्षाओं के लिए बेहतरीन समाधानों की पहचान करने में मदद करता है. डेलॉइट के सहयोग से शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'यस/सिटीज' पहल की शुरुआत दिल्ली में एक 'डिवाइन थिंकिंग एंड कोलाबोरेशन इकोसिस्टम वर्कशॉप' के साथ हुई.

समाचार विशेष

भाजपा के गढ़ में कैसे सेंध लगाएगी जन सुराज ?

पटना. पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है. बांकीपुर सीट पर सभी चार दलों ने अपने च्यत्नेख़ाल दिए हैं. एनडीए की ओर से बीजेपी ने अभिषेक बंटी, राजद ने रेखा गुप्ता, जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी और जन सुराज से ख़ुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं.

इस बांकीपुर उपचुनाव में सबकी नजरें प्रशांत किशोर पर लगी हैं. सबके मन में सवाल उठ रहा है कि भाजपा के अजेय गढ़ में जन सुराज कैसे सेंध लगाएगी ? अब इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बताई रणनीति



बताई है. प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी रणनीति बताई. उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था से है.

बांकीपुर की जनता ने नितिन नवीन को वोट दिया, सरकार के लिए नीतीश को समर्थन लिया. लेकिन दोनों ने जनता को धोखा देकर छोड़ दिया. बिहार की जनता

के मुख्यमंत्री के लिए अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिया था. ऐसे में देखा जाए तो जनता को अपनी पसंद का सीएम नहीं मिला.

हमारे लिए नहीं, सम्राट सरकार की परीक्षा है- प्रशांत किशोर- जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर का चुनाव हमारे लिए कोई टेस्ट नहीं है. असली परीक्षा तो सम्राट चौधरी की सरकार की है. उन्होंने कहा कि हम यहां चुनाव जीतने नहीं, समाज सुधारने के लिए राजनीति में आए हैं. जनता को जब विकल्प मिलेंगे, तभी वो अपनी पसंद से सही उम्मीदवार को चुन सकेंगी.

नुनाव में बांकीपुर की जनता को अपने मन की इच्छा बताएंगी: पीके बिहार का विधानसभा चुनाव आपने नहीं लड़ा था, फिर बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में क्यों उतरे ? इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है. बीजेपी के गढ़ में ही उसे चुनौती देना चाहते थे, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बांकीपुर की जनता को अपने मन की इच्छा बताएंगी, क्योंकि जनता को अपनी पसंद का सीएम चुनने का मौका नहीं मिला.

डीएमके पर रहेगा सारा दारोमदार



नई दिल्ली. ऐसा लग रहा है कि इस बार संसद के मानसून सत्र में सरकार अगर नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल लाती है तो सबसे बड़ी भूमिका एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके की रहने वाली है.

समाजवादी पार्टी के उससे ज्यादा सांसद हैं लेकिन सपा की लाइन तय है. वह विपक्ष के भाजपा है. यह अलग बात है कि भाजपा की ओर से सपा के सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है. कहा जा रहा है कि कई लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ने का

ऑफर दिया जा रहा है. कुछ सांसदों के परिवजनों को लड़ाने की बात हो रही है. लेकिन इका दुका सांसदों के टूटने से ज्यादा फर्क नहीं आएगा. क्योंकि सरकार को अब भी 360 वोट की जरूरत होगी और उसके पास 320 हैं. या तो वह 40 सांसद जुटाए या करीब 60 सांसदों को गैरहाजिर कराए तभी उसका काम होगा. तभी डीएमके की भूमिका बहुत अहम है.

गौरतलब है कि डीएमके नेता एमके स्टालिन ने परिसीमन विधेयक पर सबसे सख्त रुख अपनाया था. उन्होंने काले कपड़े पहन कर बिल की कॉपी जलाई थी. उनके सांसदों ने संसद में भी काले कपड़े पहन कर विरोध जताया था. अब सवाल है कि वे कैसे इस बिल का समर्थन करेंगे ?

विशेष क्या फिर बीजेपी का ओबीसी चेहरा बनेंगे एकनाथ खडसे ?

फडनवीस से था विवाद, अब तावड़े से मुलाकात !

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर एकनाथ खडसे चर्चा के केंद्र में हैं. एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री खडसे की भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से हुई मुलाकात ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलों को हवा दे दी है.

लंबे समय तक महाराष्ट्र भाजपा में ओबीसी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे खडसे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ बढ़ते मतभेदों के बाद पार्टी छोड़ दी थी और शरद पवार का दामन थाम लिया था. लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर भाजपा अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी है, तब



खडसे की संभावित ' घर वापसी ' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इस मुलाकात को राजनीतिक फैसला नहीं बताया है, लेकिन इस समय और राजनीतिक संकेतों ने इस बैठक को बेहद अहम बना दिया है.

उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खडसे का प्रभाव आज भी कम नहीं माना जाता. जलगांव, धुले, चालीसगांव और मनमाड़ जैसे इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ रही है. भाजपा के शुरुआती विस्तार में उन्होंने प्रमोद महाजन और दिवांत गोपीनाथ मुंडे के साथ मिलकर सालों तक संगठन खड़ा किया था. यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को, केवल औपचारिक बैठक मानने को तैयार नहीं हैं. दूसरी ओर, उनकी बेटी रोहिणी खडसे फिलहाल शरद पवार की एनसीपी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में यदि खडसे भाजपा में वापसी करते हैं तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है.

बुधवार को एकनाथ खडसे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की. इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भाजपा अपने पुराने और अनुभवी ओबीसी चेहरे को फिर से संगठन में शामिल करने की तैयारी कर रही है. फिलहाल मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. एकनाथ खडसे कभी महाराष्ट्र भाजपा की सबसे प्रभावशाली आवाजों में गिने जाते थे. संगठन निर्माण से लेकर चुनावी रणनीति तक उनकी अहम भूमिका रही. हालांकि समय के साथ उनका देवेंद्र फडणवीस से विवाद बढ़ा.

उत्तर महाराष्ट्र में अब भी मजबूत है पकड़

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों में एकनाथ खडसे का जनाधार आज भी मजबूत है . खासकर जलगांव, धुले, मनमाड़ और चालीसगांव जैसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है . ओबीसी समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है . यही कारण है कि यदि भाजपा उन्हें दोबारा साथ लाने में सफल होती है तो इसका सीधा असर क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ सकता है . एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे फिलहाल शरद पवार की एनसीपी में महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं .